भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2598

16 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

डिजिटल अभिशासन और शहरी प्रौद्योगिकी

2598. श्री मस्तान राव यादव बीडाः

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

श्री केसरीदेवसिंह झालाः

श्री एस. सेल्वागनबेथीः

श्री अमर पाल मौर्यः

श्री नारायण कोरागप्पाः

श्री उज्जवल देवराव निकमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी ऑफ़ ऑनलाइन गवर्नेंस (यूपीवाईओजी) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत किन विशिष्ट नागरिक सेवाओं को डिजिटलीकृत किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) जटिल शहरी चुनौतियों का समाधान करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का किस प्रकार समर्थन प्रदान करता है;

(ग) क्या यूपीवाईओजी प्लेटफॉर्म ने शहरी अभिशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सफलतापूर्वक बढ़ाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहर-स्तर के सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए एनयूडीएम-यूपीवाईओजी रूपरेखा का विस्तार कब तक किया जाएगा?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) प्रायोगिक परियोजना के भाग के रूप में विकसित डिलीवरी ऑफ़ ऑनलाइन गवर्नेंस के लिए अर्बन प्लेटफार्म (उपयोग) के अंतर्गत प्रमुख शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) कार्यों के डिजिटलीकरण में सहायता प्रदान करने और नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदायगी को बढ़ाने के लिए 18 मुख्य नगरीय ई-गवर्नेंस सेवाएं विकसित की गई है।

इन सेवाओं में शामिल हैं:

1. संपत्ति कर
2. अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी)
3. ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली (ओबीपीएएस)
4. व्यापार लाइसेंस (टीएल)
5. लेखा और वित्त
6. जल और सीवरेज सेवाएं
7. परिसंपत्ति प्रबंधन
8. पेट पंजीकरण
9. पथ विक्रेता प्रबन्धन
10. सामुदायिक हॉल/स्थल बुकिंग
11. निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन
12. ई-कचरा प्रबंधन
13. मल कीचड़ हटाने की सेवाएं (स्वच्छता/सेप्टेज प्रबंधन)
14. विज्ञापन/जमाखोरी अनुमतियाँ
15. नागरिक सेवा अनुरोध
16. उपयोगकर्ता शुल्क/विविध संग्रह/चालान
17. नगरपालिका शिकायत निवारण
18. जन्म और मृत्यु पंजीकरण

(ख) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) प्रायोगिक मोड में है और उपयोग प्लेटफॉर्म विकसित करके अर्बन गवर्नेंस में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जो एक ओपन-सोर्स, माइक्रो सर्विसेज-आधारित और मॉड्यूलर डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह आर्किटेक्चर इंटरऑपरेबिलिटी, आसान अनुकूलन और मौजूदा राज्य और नगरपालिका प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाता है।

उपयोग का भारत सरकार के प्रमुख डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे आधार, ई-साइन और मेरी पहचान के साथ एकीकरण किया जा सकता है। मॉड्यूलर डिजाइन शहरी स्थानीय निकायों को सेवा प्रदायगी में सुधार और जटिल शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को आसानी से अपनाने में सहायता करता है।

(ग और घ) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) (प्रायोगिक) के तहत, उपयोग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नगरपालिका सेवाओं की डिजिटल, मानकीकृत और ट्रेसेबल सेवा प्रदायगी द्वारा अर्बन गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

एनयूडीएम के वर्तमान प्रायोगिक चरण के दौरान, केन्द्रीय प्लेटफार्म को स्थायी करने और इसे राज्यों को अपनाने के लिए उपलब्ध करवाने पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान में अपने शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग प्लेटफार्म के तहत विकसित चयनित नगरपालिका सेवाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी ऑनलाइन एप्लिकेशन, डिजिटल भुगतान और स्थिति ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है, जिससे नगरपालिका सेवा प्रदायगी की पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार होता है।

(ङ) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) और उपयोग फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित स्कीम की रूपरेखा पर इस समय मंत्रालय में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

*****